✦वर्ष 02 ✦ अंक 08 ✦ मार्च- 2025 ✦रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित ✦पृष्ठ-32 ✦ मूल्य-10 रुपये

मासिक पत्रिका

RNI-CHHHIN/2023/88003

प्रदेश रौनक

Pradeshraunak.com

छत्तीसगढ़ में पहली बार हस्तलिखित बजट पेश

बजट से छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी तीव्र गति : मुख्यमंत्री

हम मकान नहीं
घर बनाते हैं

रुचि कंस्ट्रक्शन

नया बस स्टैण्ड, बालोद

अनुभवी आर्किटेक्ट/इंजीनियर के मार्गदर्शन में रेसीडेन्सियल
व कमर्शियल भवन निर्माण कार्य किया जाता है

निर्माण कार्य कराने के लिए संपर्क करें
9893162815,9406208242

बिजली फिटिंग कार्य
के लिए संपर्क करें
9752420015 ,9893259555

मासिक पत्रिका
प्रदेश रौनक
RNI-CHHHIN/2023/88003
मार्च-2025 (मासिक)
● ● वर्ष-02 ● अंक-08
● पृष्ठ-32
रायपुर (छत्तीसगढ़)
से प्रकाशित
मूल्य 10/-
संपादक
तुली मजूमदार
छायाकार
अमित राय
विशेष संवाददाता
रविशंकर पाण्डेय
ले-आउट
देवांशु-7067255727

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक **सुजाता सोम** द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पीएनबी के सामने जयस्तंभ चौक,रायपुर (छत्तीसगढ़) पिन नं. 492001 से मुद्रित कर बाबा किराना स्टोर्स के पास,कालीनगर पंडरी,रायपुर पिन नं. 492004 (छत्तीसगढ़)से प्रकाशित
* संपादक -**तुली मजूमदार**
* पी.आर.बी.एक्ट के तहत समस्त समाचार/लेखों के चयन के लिए जिम्मेदार
Email-pradeshraunak@gmail.com
मोबाइल नं.-9669576496
*(सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र रायपुर होगा)

5

बजट से छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी तीव्र गति : मुख्यमंत्री साय

4

छत्तीसगढ़ में पहली बार हस्तलिखित बजट पेश

9

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री को सौंपा बस्तर के विकास का रोडमैप

छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्रांति 3 लाख करोड़ का निवेश चार तरह के पावर प्लांट से बनेगी अपार ऊर्जा

12

छात्र जीवन सर्वश्रेष्ठ समय : डॉ. रमन सिंह

14

समाज की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक : मुख्यमंत्री

बजट में सभी को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया

कोई भी सरकार अपना बजट पेश करती है तो वह बताती है कि उसकी प्राथमिकता क्या है।वह एक साल में किस क्षेत्र में क्या नया करने वाली है, पुरानी योजनाएं क्या क्या जारी रहेंगी, उसकी नई योजनाएं क्या हैं, किस क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करने के लिए योजनाएं लाई गईं हैं।किस क्षेत्र में वह सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है किस क्षेत्र को बजट में सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है, किस वर्ग को क्या क्या दिया गया है। बजट से वर्तमान में क्या फायदा होगा और भविष्य में क्या फायदा होगा। हर सरकार बजट के लिए सभी को कुछ न कुछ देकर खुश करने का प्रयास करती है, साय सरकार ने भी अपने दूसरे १.६५ लाख करोड़ के बजट में सभी लोगों को कुछ न कुछ देकर खुश करने का प्रयास किया है। जो क्षेत्र जिस सुविधा या सेवा से वंचित है, उनको वह सुविधा और सेवा देने का प्रयास किया गया है। पीएम मोदी का परम लक्ष्य है, विकसित भारत, विकसित राज्यों से ही बनेगा इसलिए छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है किया गया है। साय सरकार के पहले बजट में ज्ञान पर जोर था, उसके दूसरे बजट में गति पर जोर दिया गया है।यानी गुड गवर्नेंस,एक्सलेरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर,टेक्नोलाजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर खास जोर दिया गया है। पिछले बजट में विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप समावेशी विकास की राह तैयार की गई थी। साय सरकार का पूरा फोकस ज्ञान यानी गरीब,युवा, अन्नदाता व नारीशक्ति पर था। ज्ञान के आधार पर सरकार ने एक साल काम किया तो इसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। अब राज्य को तेज विकास की जरूरत है, इसलिए इस बजट में गति पर जोर दिया है यानी हर क्षेत्र में विकास की तेज गति की ओर ध्यान दिया जाएगा। गति की ओर ध्यान देने का मतलब यह है कि सरकार सुशासन को और कैसे तेज किया जा सकता है,बुनियादी ढांचे को कैसे और तेजी से मजबूत किया जा सकता है।नई तकनीक का प्रयोग कर तेजी से हर क्षेत्र में कैसे विकास किया जा सकता है।इसी के साथ औद्योगिक विकास को कैसे तेज किया जा सकता है, इस ओर ध्यान देना है। हर राजनीतिक दल की सरकार राज्य के समग्र विकास का सपना देखती है, उसके पूरा करने के लिए साकार करने के लिए नई योजनाएं बनाती है,इस बजट में सरकार ने राज्य के विकास के लिए १० नई योजनाएं लेकर आई हैं।यह योजनाएं हैं-मुख्य-मंत्री नगरोत्थान योजना,सीएम बायपास,रिंगरोड योजना,मुख्य-मंत्री मोबाइल टावर योजना,छात्र स्टार्टअपनवाचार क्रियान्वयन योजना,मुख्यमंत्री परिवहन योजना,सियान केयर योजना,पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना,अटल सिंचाई योजना,मुख्यमंत्री गृहप्रवेश सम्मान योजना,मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप योजना।साय सरकार ने वर्ष २०२५ को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाएगी इसलिए इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाएगी और राज्य के विकास के लिए हर क्षेत्र मे ढेर सारे निर्माण कार्य करेगी।

किसी राज्य को विकसित राज्य बनाने के लिए राज्य की अधोसंचरना का मजबूत होना जरूरी होता है इसलिए इस बजट मे राज्य की अधोसंचरना को मजबूत करने की योजना बनाई गई है, इसके लिए हर तरह की सेवा व सुविधा के लिए काम किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास के लिए भी ज्यादा बजट दिया गया है ताकि महिलाओं को सशक्त और आगे बढ़ने का ज्यादा मौका मिले। महतारी वंदन योजना का बजट बढ़ाया गया है, इससे राज्य में इस योजना से और महिलाओ को फायदा होगा। विपक्ष इस बात के लिए सरकार की आलोचना कर रहा था कि पात्र महिलाओं के नाम पर महिलाओं के नाम महतारी वंदन योजना से काटा जा रहा है, इससे योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है। कांग्रेस का आरोप रहा है कि महतारी वंदन योजना का लाभ सभी महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है, इसलिए इस योजना में राशि बढ़ाई गई है ताकि और ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ देकर उनको सशक्त बनाया जा सके।भाजपा की जीत में महिलाओं की भूमिका भी अहम रही थी इसलिए भाजपा ने महिलाओं को सशक्त बनाने व आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई है, उन योजनाओं का जरिए महिलाएं सशक्त हो रही है, और आगे बढ़ रही हैं। राज्य की राजनीति में किसानों की भी अहम भूमिका होती है इसलिए बजट में किसानों की ओर भी खास ध्यान दिया गया है। इस बजट में कृषक उन्नति योजना के तहत १० हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत ६०० रुपए,फसल बीमा योजना के लिए ७५० करोड़,किसानों को फ्री बिजली योजना केलिए ३५०० करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।इससे किसानों को लाभ होगा,उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। इस बार महिला व किसान के साथ ही औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए बजट में खास ख्याल रखा गया है। इसके लिए उद्योग विभाग का बजट तीन गुना कर दिया गया है। व्यापार सुधार कार्ययोजना के तहत एकल खिड़की प्रणाली कार्यान्वयन होगा,सीएसआईडीसी में व्यवसाय प्रबधन साफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा, इंवेस्ट छत्तीसगढ़ के तहत राज्य में निवेशकों को बुलाया जाएगा.रोजगारपरक औद्योगिक नीति लाई जाएगी।राज्य के विकास में युवाओं की भी अहम भूमिका होती है इसलिए राज्य में युवाओं के लिए राज्य छात्रवृत्ति योजना के लिए १५० रोड़ रखे गए हैं।उनके लिए पुस्तकालय, कौशल विकास योजना, स्टार्टअप आदि खोलने के लिए पर्याप्त बजट रखा गया है। शिक्षा के लिए एजुकेशन सिटी के साथ ही केंद्रीय पुस्तकालय,राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,फिजियोथेरेपी कालेज,नर्सिंग कालेज खोलने की व्यवस्था में बजट मे की गई है। इसी तरह स्वास्थ्य,परिवहन, सड़क, खेलकूद,धार्मक आयोजन आदि के लिए सरकार ने बजट प्रावधान किया है।

बजट से छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी तीव्र गति : मुख्यमंत्री साय

रायपुर ▸▸प्रदेश रौनक

यह बजट वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य में विकसित छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। इस बजट से छत्तीसगढ़ के विकास को तीव्र गति मिलेगी। इसमें धान के कटोरे की चमक ''कृषि अर्थव्यवस्था'' को संवारने के उपायों के साथ ही इंडस्ट्रियल हब और आईटी हब के रूप में छत्तीसगढ़ को तैयार करने की ठोस नींव रखी गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज विधानसभा में अपनी सरकार के दूसरे साल के प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उपरोक्त बातें कही। साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमने छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम आधुनिक समय के मुताबिक अपनी अर्थव्यवस्था को तैयार करें, बजट में पूरा फोकस इसी पर है। हमने राजकोषीय सुधारों के साथ प्रशासनिक प्रणालियों में सुधार करते हुए बजट के संतुलित उपयोग से प्रदेश में जनकल्याण के कार्य पुनः आरंभ कराए। अब छत्तीसगढ़ में विकास ट्रैक पर आ गया है और ट्रिपल इंजन की सरकार इसे तेजी से गति दे रही है। बजट प्रावधानों से यह गति और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले बजट में विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप समावेशी विकास की राह तैयार हुई और हमारा फोकस ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति पर था। इनके लिए हमने जिस तरह से नवाचारी योजनाएं लागू कीं, उसके प्रभावी नतीजे मिले। इस बार बजट का थीम है ''ज्ञान के लिए गति'' यह हमारी ट्रिपल इंजन सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि गति से हमारा तात्पर्य सुशासन, बुनियादी ढांचे में तेजी लाना, तकनीक का अधिकाधिक प्रयोग और औद्योगिक विकास में तीव्र वृद्धि करना है। हम इन सभी मानदंडों को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए हमने बड़े सपने देखे हैं और उन्हें पूरा करने की रणनीति भी तैयार कर ली है। इन्हें पूरा करने के लिए हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी रफ्तार से काम करेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण भी किया। उन्होंने कहा कि उनके जन्म शताब्दी वर्ष को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटल जी छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की श्रेणी में देखना चाहते थे, उनके सपनों को पूरा करने की ठोस नींव हमने रख दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी अधोसंरचना की जरूरत होगी जो एक विकसित औद्योगिक राज्य की जरूरतों को पूरी करती हो। इसके लिए हमने बजट में विशेष प्रावधान किये हैं। रायपुर-दुर्ग मेट्रो सेवा का सर्वे होगा। नये औद्योगिक पार्क स्थापित कर रहे हैं। इसके लिए 700 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। महानदी- इंद्रावती तथा कोडार-सिकासर जैसी नदियों को जोड़ेंगे, खेती में निवेश करेंगे। नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट के साथ हमारा प्रदेश नये संकल्पों के साथ अपने सपनों को पूरा करने एक नई उड़ान भरेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बजट में मानव संसाधन को सहेजने के लिए नये अस्पतालों, आधुनिक स्कूलों और इनमें पर्याप्त स्टाफ के संबंध में व्यवस्था की है। राज्य की नई औद्योगिक नीति की जरूरतों को पूरा करने 12 नए इंजीनियरिंग कालेज और 12 पालिटेक्निक कालेज आरंभ करेंगे। नये बिजनेस और स्टार्टअप के लिए 700 करोड़ रुपए का इंडस्ट्रियल सब्सिडी सपोर्ट रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार पूंजीगत व्यय 26 हजार करोड़ रुपए से अधिक रखा गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत है। पूंजीगत व्यय में किये गये निवेश का कई गुना रिटर्न मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट समावेशी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के हमारे ध्येय के मुताबिक तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों के अनुरूप हमने अंत्योदय के कल्याण के लिए तथा इनके समग्र विकास के लिए विशेष बजट प्रावधान रखा है। पिछले बजट में गरीब युवा, अन्नदाता तथा नारी शक्ति एवं जनजातीय विकास के लिए जो योजनाएं आरंभ की गई थी, उनके लिए बजट प्रावधान के साथ ही इनके विकास के लिए नई योजनाएं भी इस बजट में आरंभ की गई है।

छत्तीसगढ़ में पहली बार हस्तलिखित बजट पेश

रायपुर ▶▶प्रदेश रौनक

छत्तीसगढ़ विधानसभा में ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने हस्तलिखित बजट पेश किया। यह पहला मौका है जब राज्य में कंप्यूटर-टाइप्ड बजट की जगह खुद वित्त मंत्री के हाथों से लिखा गया बजट सदन में प्रस्तुत किया। यह बजट 100 पृष्ठों की है, जिसे पूरी तरह हाथ से लिखा गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे परंपराओं की ओर वापसी और मौलिकता को बढ़ावा देने का कदम बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में हस्तलिखित बजट पेश करना एक अलग पहचान और ऐतिहासिक महत्व रखता है।

नई परंपरा की शुरुआत-अब तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में केवल कंप्यूटर-टाइप्ड बजट ही पेश किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार परंपरागत और अनूठे अंदाज में बजट तैयार किया गया। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी का मानना है कि इससे प्रामाणिकता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

बजट में आम जनता और सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

रायपुर ▸▸ प्रदेश रौनक

छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में जनता को राहत देने वाले कई अहम फैसले किए हैं। पेट्रोल की कीमत में 1 प्रति लीटर की कमी की गई है, जिससे आम लोगों, किसानों और उद्योगों को लाभ होगा। इसके पहले सरकार ने

थोक में डीजल खरीदी पर वैट घटाकर 17% कर दिया था, जिससे परिवहन और कृषि कार्यों की लागत में कमी आई है। वहीं, राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी की गई है, जो मार्च से लागू होगी। छत्तीसगढ़ का बजट प्रदेश को डिजिटल, सुरक्षित और विकसित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर, गांवों के विकास, शहरों में नई सुविधाओं और सुरक्षा तक हर क्षेत्र में सरकार ने कुछ नया किया है। आने वाले सालों में छत्तीसगढ़ और आगे बढ़ेगा और देश के सबसे उन्नत राज्यों में शामिल होगा। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने से ट्रैक्टर, पंप सेट और अन्य कृषि यंत्रों की लागत घटेगी, जिससे किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। इसके अलावा, चावल मिल, गन्ना फैक्ट्री और अन्य कृषि आधारित उद्योगों के लिए परिवहन और उत्पादन खर्च कम होगा, जिससे आवश्यक वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं।

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों की आय बढ़ेगी, जिससे उनकी क्रय शक्ति और बाजार में मांग बढ़ेगी। सरकार का यह फैसला आम जनता, किसानों और व्यापारियों के लिए राहत लेकर आया है और इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया पेंशन फंड पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशन फंड बनाया है, ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षित रहे। साथ ही, देश में पहली बार छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाया जा रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

अब हर गांव में मोबाइल टॉवर और पब्लिक बसें

गांवों में रहने वाले कई लोगों को फोन नेटवर्क नहीं मिलता। सरकार अब मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना लेकर आई है, जिससे जंगलों और पहाड़ों में बसे गांवों में भी मोबाइल का नेटवर्क मिलेगा। इससे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे और लोग अपने रिश्तेदारों से आसानी से बात कर सकेंगे।इसके अलावा, कुछ गांवों में पब्लिक बसें नहीं चलतीं, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग कम होते हैं। अब सरकार मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत ऐसी जगहों पर भी बसें चलाने जा रही है, ताकि गांव से ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक लोग आसानी से आ-जा सकें।

शहरों का मेकओवर: नए अस्पताल, कॉलेज और मेट्रो

छत्तीसगढ़ के शहरों को और सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट्स ला रही है:

- नवा रायपुर में मेडिसिटी एक ऐसा शहर जहाँ सबसे अच्छे अस्पताल होंगे।
- एजुकेशन सिटी यहाँ हर तरह की पढ़ाई के लिए बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी

बनाई जाएंगी।

- राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (NIFT) जो बच्चे फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक खास कॉलेज खुलेगा।
- रायपुर-दुर्ग मेट्रो- अब बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन का सर्वे किया जाएगा, ताकि भविष्य में मेट्रो सेवा शुरू हो सके।

सुरक्षा और पर्यटन: नई योजनाएं

- NSG की तर्ज पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) यह एक खास पुलिस टीम होगी, जो खतरनाक अपराधियों से निपटेगी।
- अब राज्य में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF) का गठन होगा, जो CISF की तर्ज पर काम करेगा। इससे राज्य में उद्योगों और महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा मजबूत होगी।
- छत्तीसगढ़ का पहला आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन रही है, जहाँ जंगल, पानी और वाइल्डलाइफ का मज़ा मिलेगा! सरकार 200 करोड़ रुपये खर्च करके नया पर्यटन स्थल बनाने जा रही है।

पत्रकारों के लिए सरकार ने किया बड़ा फैसला

- पत्रकारों की एक्सपोजर विजिट के लिए बजट
- पत्रकार संघ के दफ्तरों के नवीनीकरण के लिए पैसे
- पत्रकार सम्मान निधि दोगुनी कर दी गई है!

गाँव-गाँव तक चमकेंगी पक्की सड़कें

- अब गांवों की सड़कें और मजबूत और बेहतर होंगी। इसके लिए –
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 845 करोड़
- जनजातीय क्षेत्रों की सड़कें 500 करोड़
- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना – 119 करोड़
- मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना शुरू की जाएगी, इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान
- नई सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान।

शहर और गाँव दोनों होंगे स्मार्ट

- नगर पालिकाओं का विकास 750 करोड़ (हर शहर को और सुंदर बनाया जाएगा)
- नगर निगमों में सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू की जाएगी, 500 करोड़ का प्रावधान
- नई फायर स्टेशन्स के लिए 44 करोड़ (सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत)
- मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान

बस्तर-सरगुजा में पर्यटन और एडवेंचर की दुनिया

अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं या घर से दूर प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं, तो सरकार ने आपके लिए बस्तर और सरगुजा में होमस्टे पॉलिसी लागू की है। अब यहां आने वाले पर्यटक गांवों में रहकर स्थानीय संस्कृति और खानपान का अनुभव ले सकेंगे। इसके अलावा, जशपुर में एडवेंचर टूरिज्म और टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा, जिससे वहां आने वाले लोगों को और भी मजा आएगा।

नालंदा लाइब्रेरी और विज्ञान पार्क: छात्रों के लिए नया तोहफा

छात्रों की पढ़ाई को और रोचक बनाने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु अनुकूल माहौल देने के लिए 17 और नालंदा लाइब्रेरी खोली जाएंगी। यही नहीं, विज्ञान में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए बस्तर और सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब शुरू की जाएगी और साइंस पार्क की स्थापना सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, जशपुर और रायगढ़ में होगी। अब बच्चों को किताबों से बाहर निकलकर विज्ञान को प्रयोगों के माध्यम से सीखने का मौका मिलेगा।

कृषि और डिजिटल तकनीक का संगम

अब किसानों को भी डिजिटल सुविधा मिलेगी! भूमि अभिलेखों (Land Records) के डिजिटलीकरण और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए विशेष फंड दिया गया है। इससे किसानों को अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी तुरंत मोबाइल या कंप्यूटर पर मिल सकेगी।

स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार

राज्य के गरीब और निःसंतान दंपतियों के लिए रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ART सुविधा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही, सरकारी अस्पतालों में MRI और CT स्कैन मशीनों के लिए भी बजट रखा गया है, ताकि मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके। सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा जशपुर व मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी व नेचुरोपैथी के सेंटर स्थापित किए जाएंगे

बिना कागज के होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन

अब जमीन या मकान खरीदने-बेचने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी! सरकार ने फेसलेस और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे।

चिकित्सा और खाद्य सुरक्षा में बड़ा कदम

रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की इंटीग्रेटेड फूड एंड ड्रग लैबोरेटरी बनाई जाएगी, जिसमें दवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। नक़ली दवाओं और मिलावट करने वालों पर कार्रवाई के लिए सरकार का बड़ा क़दम है।

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई योजना

छत्तीसगढ़ सरकार पहली बार सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल पेमेंट (UPI) को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट का प्रावधान कर रही है। इससे गाँवों में भी लोग आसानी से डिजिटल लेनदेन कर सकेंगे और नकद लेनदेन की जरूरत कम होगी।

पहली बार 'आइकॉनिक डेस्टिनेशन' और 'वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वॉटर टूरिज्म' विकसित होगा-छत्तीसगढ़ में पहली बार 'आइकॉनिक डेस्टिनेशन' और 'वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वॉटर टूरिज्म' के लिए 200 करोड़ का बजट रखा गया है। इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यह एक बड़ा आकर्षण केंद्र बनेगा।

व्यवसायियों एवं आम आदमी को राहत

बजट में अचल संपत्ति के अंतरण पर मुद्रांक शुल्क के 12 प्रतिशत सेस को समाप्त किया गया है। इससे आम जनता को लाभ मिलेगा। वहीं, ई वे बिल जनरेट करने की मूल्य सीमा को 50 हजार रुपए से बढ़ा कर 1 लाख रुपए की गई है।

वर्किंग वूमेन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने की बड़ी घोषणा

छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट 2025 में वर्किंग वूमेन के लिए बड़ी घोषणा की है. सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेशभर में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करने के लिए 7 वर्किंग वूमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे. इस परियोजना के लिए 79 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती आवास प्रदान करना होगा. साय सरकार द्वारा प्रस्तावित इन हॉस्टलों में सुरक्षा, स्वच्छता और आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर हॉस्टल बनाया जाएगा. इनमें 24×7 सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी समेत अन्य कई सुविधाएं हो सकती है.

100 एकड़ में बनेगी एडुसिटी और 100 एकड़ में बनेगी मेडिसिटी

100 एकड़ में एडुसिटी बनने से यहां प्रदेश के लाखों बच्चों को शिक्षा और शोध के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेगी. इतना ही नहीं इसके बनने से आधुनिक शिक्षा और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनेगा. वहीं बजट में मेडिसिटी बनाने की भी घोषणा की गई है. यह परियोजना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगी, जिससे राज्य के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी. इसके तैयार होने से छत्तीसगढ़ में हेल्थ सुविधाओं में वृद्धि होगी. मेडिसिटी की स्थापना से नवा रायपुर अटल नगर में प्रदेश वासियों को एक ही स्थान पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी.

दंतेवाड़ा में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज, 'GATI' मॉडल पर होगा राज्य का विकास

रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर रही है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि इस बार का बजट 'GATI' मॉडल पर आधारित है. सरकार इसके माध्यम से विकास की नई दिशा में आगे

बढ़ेगी. इस दौरान मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि DMF फंड से दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा. सरकार 250 करोड़ रुपये की लागत से दंतेवाड़ा में नया मेडिकल कॉलेज खोलेगी. छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 14 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 11 सरकारी और 3 निजी संस्थान हैं. हाल ही में कवर्धा, मनेंद्रगढ़, जांजगीर-चांपा और गीदम में चार नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है, जिससे राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है. इन नए कॉलेजों के साथ राज्य में एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या 1,820 से बढ़कर 2,320 हो गई है. अब सरकार दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है. विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार का बजट GATI पर आधारित है.

डोंगरगढ़ को बजट में बड़ी सौगात

छत्तीसगढ़ सरकार ने डोंगरगढ़ को मध्य भारत का एक बड़ा धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिहाज से बजट 2025 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. इन घोषणाओं के अमलीजामा पहनने से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने दूसरे बजट में डोंगरगढ़

परिक्रमा पथ (कॉरिडोर) और Y शेप ओवरब्रिज के निर्माण की घोषणा की. इसके अलावा केंद्र सरकार की "प्रसाद योजना" का नाम बदलकर "मां बम्लेश्वरी तीर्थ विकास योजना" कर दिया गया है. इस योजना के तहत मंदिर पहाड़ी के चारों ओर परिक्रमा पथ (कॉरिडोर) और श्री यंत्र की आकृति में एक भव्य मोटेल का निर्माण किया जाएगा.

डोंगरगढ़ को वैश्विक तीर्थ स्थल बनाने की पहल–डोंगरगढ़ पहले से ही हिंदू और बौद्ध धर्म का आस्था केंद्र रहा है. लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि के बाद यह जैन धर्मावलंबियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुका है. सरकार द्वारा घोषित ये योजनाएं डोंगरगढ़ को अंतरराष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं. हर साल लाखों श्रद्धालु मां बम्लेश्वरी मंदिर और अन्य तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए यहां आते हैं. इन विकास कार्यों से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही डोंगरगढ़ का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व और अधिक बढ़ेगा.

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हाथों से लिखा 100 पेज का बजट, समर्पण और प्रतिबद्धता की मिसाल

रायपुर. आजकल जहां अदालती फैसले भी एआई संचालित चैटबॉट का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हिंदी में 100 पेजों का हाथों से लिखा बजट पेश कर बड़ा संदेश लोगों को दिया है. हाथों से लिखा गया उनका बजट ये बताता है कि वो अपने काम को कितने समर्पित भाव से पूरा करते हैं. छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री के हाथों से लिखे बजट की तारीफ आज देशभर में की जा रही है. 3 मार्च को छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया गया था.

ओपी चौधरी की हो रही तारीफ :- वित्त मंत्री ओपी चौधरी एक पूर्व आईएएस हैं जिन्होंने राजनीति में शामिल होने के लिए प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़ी. ओपी चौधरी ने प्रशासनिक सेवा छोड़ कर जनता की सीधी सेवा करने का फैसला लिया. 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरु हुआ था. तीन मार्च को बजट पेश किया गया. बजट की कॉपी को तैयार करने के लिए ओपी चौधरी ने आधी आधी रात तक जगकर काम किया. बजट की कॉपी लिखने के दौरान वो कई रात महज 2 घंटे ही सो पाए. कंप्यूटर के जमाने से में इस तरह से हाथों से बजट को लिखकर सदन में पढ़ना बड़ी बात है.

मैं अपना भाषण लिख रहा था और मुझे एहसास हुआ कि एक हस्तलिखित दस्तावेज़ मेरी भावनाओं, मेरी भावनाओं, मेरे दृष्टिकोण, मेरी प्रतिबद्धता और मेरे लगाव को अधिक व्यक्त करता है। और इसलिए, मैंने सोचा, मुझे अपनी हस्तलिपि में लिखना चाहिए – ओपी चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़

एक से डेढ़ घंटे की नींद ली :- ओपी चौधरी कहते हैं कि बजट पर 5 से 6 महीने से काम चल रहा था, लेकिन बजट के घटकों पर वास्तविक लेखन प्रस्तुति से लगभग एक सप्ताह या 10 दिन पहले शुरू हुआ. मैं सचमुच चार रातों तक नहीं सोया. मैं उन चार रातों में मुश्किल से 1-1.5 घंटे सोया.

2005 बैच के आईएएस अधिकारी: 2005 बैच के आईएएस अधिकारी चौधरी ने 2018 में भाजपा में शामिल होने के लिए रायपुर कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था। हिंदी पर उनकी मजबूत पकड़, एक विषय जिसे उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के दौरान पढ़ा था, ने उन्हें अपनी पसंदीदा शैली में बजट लिखने में मदद की. अपने नौकरशाही जीवन के 13 वर्षों के दौरान, मैंने पूरी लगन के साथ काम किया, अपना 100 प्रतिशत दिया. मैं अपने करियर के चरम पर था. मैं रायपुर राजधानी का कलेक्टर था. मेरे दिमाग में एक विचार आया कि भारत में इतना विकास है, भारत में इतने अवसर हैं. भारत में इतना कुछ करने के इतने अवसर हैं. इसलिए, मैंने सोचा कि अगर सिविल सेवाओं से बड़ा कोई मंच है तो वह राजनीति है

ओपी चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़

राजनीति सेवा का बड़ा माध्यम :- ओपी चौधरी कहते हैं कि नौकरशाह होने की तुलना में राजनीति लोगों के जीवन पर बड़ा प्रभाव डालने का एक बड़ा माध्यम है. चौधरी कहते हैं कि मैंने बचपन में पढ़ा था कि अच्छे लोगों के राजनीति में न आने का नतीजा यह होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर राज करते हैं। इसलिए, मैं इस विचार से प्रेरित हुआ और राजनीति में आने का फैसला किया. चौधरी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व से प्रभावित थे और इसी वजह से राजनीति में आए. 2018 में ओपी चौधरी ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गए. 2023 में रायगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लड़े और जीते.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री को सौंपा बस्तर के विकास का रोडमैप

नई दिल्ली ▸▸ प्रदेश रौनक

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात कर राज्य के विकास संबंधी विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बस्तर विकास के मास्टर प्लान का खाका प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर विकास का मास्टर प्लान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाओं, उद्योगों और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की रूपरेखा शामिल थी। प्रधानमंत्री ने इस योजना पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सुरक्षा बलों की संगठित रणनीति एवं जनभागीदारी के चलते नक्सल प्रभावित इलाकों में तेजी से बदलाव आ रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस और केंद्रीय बलों के संयुक्त प्रयासों से कई नक्सल गढ़ों में विकास की किरण पहुंची है, जिससे जनता का विश्वास सरकार की योजनाओं में और मजबूत हुआ है। सरकार का अब पूरा ध्यान बस्तर को नए औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने पर है, जिससे युवाओं को रोजगार और आदिवासी समुदायों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य की नई औद्योगिक नीति और निवेशकों की बढ़ती रुचि पर भी विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि निवेश को आसान बनाने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस, टैक्स छूट और अनुकूल नीतियों को लागू किया है, जिससे बड़ी कंपनियां छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आकर्षित हो रही हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मुलाकात में महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया जा रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। मुख्यमंत्री ने बैठक में बस्तर की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। उन्होंने बताया कि बस्तर के महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हजारों महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लघु वनोपज, जैविक कृषि, हथकरघा, बांस उद्योग और हस्तशिल्प को प्रोत्साहित कर महिलाओं को न केवल आजीविका के साधन मिल रहे हैं, बल्कि वे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रही हैं। इसके अलावा, स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों के माध्यम से बस्तर की महिलाओं को उत्पादन और विपणन से जोड़ने की पहल की जा रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सकें।

प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा, बड़े विकास कार्यों का होगा शुभारंभ

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 30 मार्च को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ दौरे की रूपरेखा साझा की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की और प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया।

छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्रांति 3 लाख करोड़ का निवेश चार तरह के पावर प्लांट से बनेगी अपार ऊर्जा

'छत्तीसगढ़ एनर्जी इंवेस्टर्स समिट' में अदानी, जिंदल और एनटीपीसी समेत कई कंपनियों ने किया निवेश का ऐलान

रायपुर ▶▶प्रदेश रौनक

छत्तीसगढ़ अब ऊर्जा क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज रायपुर में हुए 'छत्तीसगढ़ एनर्जी इंवेस्टर्स समिट' में कई बड़ी कंपनियों ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है. इस निवेश से राज्य में परमाणु, थर्मल, सौर और पंप्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इससे न केवल उद्योगों को फायदा मिलेगा, बल्कि आम लोगों को भी सस्ती और निरंतर बिजली मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के क्षेत्र में यह निवेश राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बने, बल्कि पूरे देश के लिए एक ऊर्जा हब के रूप में स्थापित हो।

छत्तीसगढ़ पहले से ही 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है, जो देश के औसत से ज्यादा है। अब हर व्यक्ति को 2048 किलोवाट-घंटे बिजली मिल रही है, जिससे राज्य की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो रही हैं।

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एनटीपीसी ने 80,000 करोड़ रुपये की लागत से 4200 मेगावाट क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाने की योजना बनाई है। इससे छत्तीसगढ़ में परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन की शुरुआत होगी। थर्मल पावर क्षेत्र में भी बड़े निवेश की घोषणा हुई है। अदानी पावर 66,720 करोड़ रुपये खर्च कर कोरबा, रायगढ़ और रायपुर में 1600-1600 मेगावाट के तीन थर्मल पावर प्लांट लगाएगा। जिंदल पावर रायगढ़ में 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 12,800 करोड़ रुपये का निवेश करेगा, जबकि सरदा एनर्जी रायगढ़ में 660 मेगावाट क्षमता के प्लांट के लिए 5,300 करोड़ रुपये लगाएगी। इसके अलावा, सरकारी कंपनियां एनटीपीसी और सीएसपीजीसीएल 41,120 करोड़ रुपये की लागत से 4500 मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता मिली है। जिंदल पावर और एनटीपीसी ग्रीन मिलकर 10,000 करोड़ रुपये खर्च कर 2500 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन करेंगे। इसमें डोलेसरा में 500 मेगावाट और रायगढ़ में 2000 मेगावाट के सौर प्लांट शामिल होंगे। किसानों के लिए भी खुशखबरी है। पीएम कुसुम योजना के तहत 4100 करोड़ रुपये की लागत से 675 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन किया जाएगा और 20,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। इससे किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती बिजली मिलेगी और डीजल पंपों की जरूरत कम होगी। इसके अलावा, 57,046 करोड़ रुपये की लागत से 8700 मेगावाट क्षमता के पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे। इसमें एसजेएन कोटपाली में 1800 मेगावाट और जिंदल रिन्यूएबल द्वारा 3000 मेगावाट के प्रोजेक्ट शामिल हैं।

थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मिला निवेश प्रस्ताव

57,000 करोड़ की जलविद्युत परियोजनाएं, नदियों से बनेगी बिजली

सुकमा के ग्रामीणों ने पहली बार राजधानी का किया भ्रमण, विधानसभा कार्यवाही देखकर हुए उत्साहित

रायपुर ▶▶प्रदेश रौनक

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के दूरस्थ गांवों से आए युवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के तहत नियद नेल्लानार

योजना में शामिल सिलगेर, पूवर्ती, एलमागुंडा, लखापाल, शालातोंग, साकलेर, छोटेकेडवाल, बगडेगुड़ा और बेदरे जैसे गांवों के 119 युवा पहली बार अपने गांव से बाहर निकले और राजधानी रायपुर पहुंचे।इस शैक्षणिक भ्रमण के दौरान युवाओं ने रेलवे स्टेशन, छत्तीसगढ़ विधानसभा और वनवासी कल्याण आश्रम का दौरा किया। राजधानी आगमन के दौरान युवाओं ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का भ्रमण किया और दर्शक दीर्घा में बैठकर सदन की कार्यवाही देखी, जिससे वे बेहद उत्साहित नजर आए। इस अवसर पर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा से भेंट की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने युवाओं से चर्चा करते हुए कहा कि युवा चाहें तो अपने गांव में अमन-चैन और विकास की रोशनी फैला सकते हैं।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने युवाओं से उनके गांव की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनके गांवों में पक्की सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल, राशन, चिकित्सा और आवास जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की और कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में हम सभी मिलकर छत्तीसगढ़ को विकसित और समृद्ध राज्य बनाएंगे। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने नियद नेल्लानार योजना के तहत गांवों के आर्थिक विकास के लिए विशेष रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इन गांवों के निकट नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं, जिससे माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे। उल्लेखनीय है कि आजादी के 75 साल बाद पहली बार अपने गांव से बाहर निकल कर राजधानी पहुंचे अनेक ग्रामीणों ने प्रदेश की प्रगति को नजदीक से देखा और भविष्य में अपने गांवों के विकास में योगदान देने की इच्छा व्यक्त की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में दूरस्थ क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचे और वहां के लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। राज्य सरकार प्रदेश के माओवाद प्रभावित इलाकों में तेजी से बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अब इन दूरस्थ गांवों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना और नियद नेल्ला नार योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे ग्रामीण युवाओं को प्रदेश की विकास प्रक्रिया से जोड़ने में मदद मिल रही है। यह पहल न केवल इन गांवों के युवाओं के लिए एक नई आशा की किरण लेकर आई है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य की भी झलक देती है।

युवा चाहें तो अपने गांव में अमन-चैन और विकास की रोशनी फैला सकते हैं।

छात्र जीवन सर्वश्रेष्ठ समय : डॉ. रमन सिंह

छात्र जीवन व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ समय होता है, जो वापस नहीं आता, इसलिए विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। उन्होने छत्तीसगढ़ के युवाओं की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि वे अमेरिका, यूरोप सहित दुनिया के बड़े संस्थानों में अपनी बुद्धिमत्ता से देश का नाम रोशन कर रहे हैं।

राजनांदगांव ▸▸प्रदेश रौनक

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर सांसद संतोष पांडेय, महापौर मधुसूदन यादव, प्रशासनिक अधिकारी, समाजसेवी, प्राध्यापक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। डॉ. सिंह ने महाविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नेक) द्वारा बीप्लस प्लस ग्रेड मिलने पर बधाई दी और इसे गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ समय होता है, जो वापस नहीं आता, इसलिए विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। उन्होने छत्तीसगढ़ के युवाओं की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि वे अमेरिका, यूरोप सहित दुनिया के बड़े संस्थानों में अपनी बुद्धिमत्ता से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने नवीन शिक्षा नीति को रोजगारोन्मुख बताते हुए कहा कि इससे युवाओं के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। साथ ही, उन्होंने महाविद्यालय में अधोसंरचना सुधार, नए कक्षों के निर्माण, नियमित स्टाफ की नियुक्ति और अन्य सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान करने की घोषणा की। इस अवसर पर प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में लुमिना, कल्याणी, सोनम चंद्राकर, आंचल कसार, ओमेश्वरी, धनश्री चंचल सोनटेके, लक्ष्मी साहू, सुनील कुमार साकरे, योगिता, नम्रता द्विवेदी, दीपांशु साहू, साहिल राय, अशुतोष उपाध्याय, एकता वर्मा, तरूण कुमार, कार्तिका साहू, मिथलेश साहू, भाविका साहू सहित अन्य छात्र शामिल थे। सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि डॉ. रमन सिंह के प्रयासों से राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, जिससे क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हुई हैं। उन्होंने महाविद्यालय के रिकॉर्ड रूम के लिए 55 हजार रुपये और साइकल स्टैंड के लिए 25 लाख रुपये देने की घोषणा की। महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि जिले के प्रमुख महाविद्यालयों कमला कॉलेज, दिग्विजय कॉलेज और शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय में विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल रही है। उन्होंने महाविद्यालय की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम में कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसडीएम खेमलाल वर्मा, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. निर्मला उमरे, जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष रवि सिन्हा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उप निरीक्षक संवर्ग में चयनित अभ्यर्थियों को प्रदान किया नियुक्ति पत्र

रायपुर ▸▸ प्रदेश रौनक

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी, चंदखुरी में उप निरीक्षक संवर्ग के 840 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कहा कि राज्य में पुलिस बल की क्षमता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पुलिस का कार्य केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण निर्मित हो, यह सुनिश्चित करना भी पुलिस विभाग की महती जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल का कार्य लोगों के बीच शांति, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना भी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। तकनीकी संसाधनों के समावेश से पुलिस बल को अधिक दक्ष और प्रभावी बनाया जा रहा है।उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में पुलिस बल के सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्दी का अर्थ केवल अधिकार नहीं, बल्कि समाज की सेवा और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने नव नियुक्त पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे अपनी वर्दी का सम्मान करें और इसे हमेशा गर्व से धारण करें। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने जशपुर, रायगढ़, जगदलपुर और दंतेवाड़ा में नए महिला थानों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इन थानों के माध्यम से महिलाओं को अधिक सुरक्षित वातावरण और त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस बल को और अधिक सशक्त बनाने के लिए नई योजनाओं पर विचार कर रही है। इन योजनाओं के तहत तकनीकी उन्नयन, आधुनिक हथियारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम ने नव नियुक्त अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह पुलिस सेवा में उनके सफर की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि एक सशक्त पुलिस अधिकारी बनने के लिए उच्च मनोबल और अनुशासन अनिवार्य है। इस अवसर पर आरंग विधायक श्री गुरु खुशवंत साहेब, अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज पिंगुआ सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

समाज की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक : मुख्यमंत्री

उत्पीड़ित एवं संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल सुविधा की शुरुआत किया जिसके तहत वे ऑनलाइन एवं मोबाइल एप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकेंगी।

रायपुर ▸▸प्रदेश रौनक

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित वृहद महतारी वंदन सम्मेलनर में शामिल हुए और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की सभी महिलाओं को शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल एक विचार नहीं, बल्कि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बनें, इसके लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महिलाओं के त्याग और समर्पण के बिना कोई भी समाज और राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भारत में मातृशक्ति की पूजा की परंपरा सदियों पुरानी है और छत्तीसगढ़ सरकार इस परंपरा को और सशक्त कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कोई भी समाज तब तक संपूर्ण नहीं हो सकता जब तक समाज की महिलाएँ सशक्त न हों। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सम्मानित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और आने वाले समय में भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई नए कदम उठाए जाएँगे। महिला सशक्तिकरण की यह यात्रा सतत जारी रहेगी, क्योंकि नारी शक्ति ही राष्ट्र की शक्ति है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम-मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार महिला कल्याण के लिए महतारी वंदन योजना के तहत पिछले 13 महीनों से प्रति माह 1,000 रुपये की राशि सीधे महिलाओं के

बैंक खातों में अंतरित कर रही है। अब तक 70 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 8,488 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए भी एक नई पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब से उनका मानदेय सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे भुगतान में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित होगी। चार नए पोर्टल और डिजिटल पहल की लॉन्चिंग-मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर उत्पीड़ित एवं संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल सुविधा की शुरुआत किया जिसके तहत वे ऑनलाइन एवं मोबाइल एप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकेंगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री श्री साय ने बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के पोर्टल, इंफ्रा पोर्टल तथा स्थापना पोर्टल का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से महिलाओं को अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

महिला स्व-सहायता समूहों के लिए नए अवसर

महिला मड़ई में लगे स्टॉल्स के संबंध में मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि अब तक 15 से 20 लाख रुपये से अधिक की खरीद-बिक्री हो चुकी है, जो महिला उद्यमिता को दर्शाता है। उन्होंने घोषणा की कि नवा रायपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से ₹यूनिटी मॉल₹ बनाया जाएगा, जहाँ महिला स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को बेचने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे।

महिलाओं के लिए आरक्षण और नए अवसर

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान से लाखों महिलाओं को लाभ मिल रहा है।पंचायती राज संस्थाओं में पहले से ही महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। अब विधानसभा और लोकसभा में भी 33% आरक्षण का लाभ जल्द ही महिलाओं को मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज महिलाएँ राजनीति से लेकर फाइटर प्लेन उड़ाने और रेल संचालन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

सखी वन स्टॉप सेंटर की एसओपी छत्तीसगढ़ बना पहला राज्य

मुख्यमंत्री श्री साय ने सखी वन स्टॉप सेंटर की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का विमोचन किया और बताया कि छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि सखी वन स्टॉप सेंटर संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता प्रदान करता है। अब इस सेंटर के व्यवस्थित संचालन के लिए एक मानक प्रक्रिया बनाई गई है, जिससे इसकी प्रभावशीलता और बढ़ेगी।

महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में विशेष प्रावधान

कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार महिला सशक्तिकरण को केवल एक नारा नहीं, बल्कि अपनी नीति और संकल्प का अभिन्न हिस्सा मानती है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के राज्य बजट में महिलाओं और समाज कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं को सशक्त किया गया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर, उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा तक हर क्षेत्र में सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है।

अजेय नारी - आराध्य नारी" थीम पर हुआ महिला मड़ई का आयोजन

चार दिवसीय महिला मड़ई का आयोजन अजेय नारी - आराध्य नारी₹ थीम पर किया गया। इसमें राज्य के 33 जिलों से आए 87 महिला स्व-सहायता समूहों ने अपने हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी और विक्रय किया।इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को भी विभिन्न माध्यमों से आमजन के सामने प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत, विधायक श्रीमती गोमती साय, विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, विधायक गुरु खुशवंत साहेब, बाल संरक्षण आयोग की सदस्य श्रीमती पुष्पा पाटले, संभाग आयुक्त श्री महादेव कावरे, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, संचालक श्री जन्मजेय महोबे, रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह और आयुक्त नगर निगम श्री विश्वदीप सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और महिलाएँ उपस्थित रहीं।

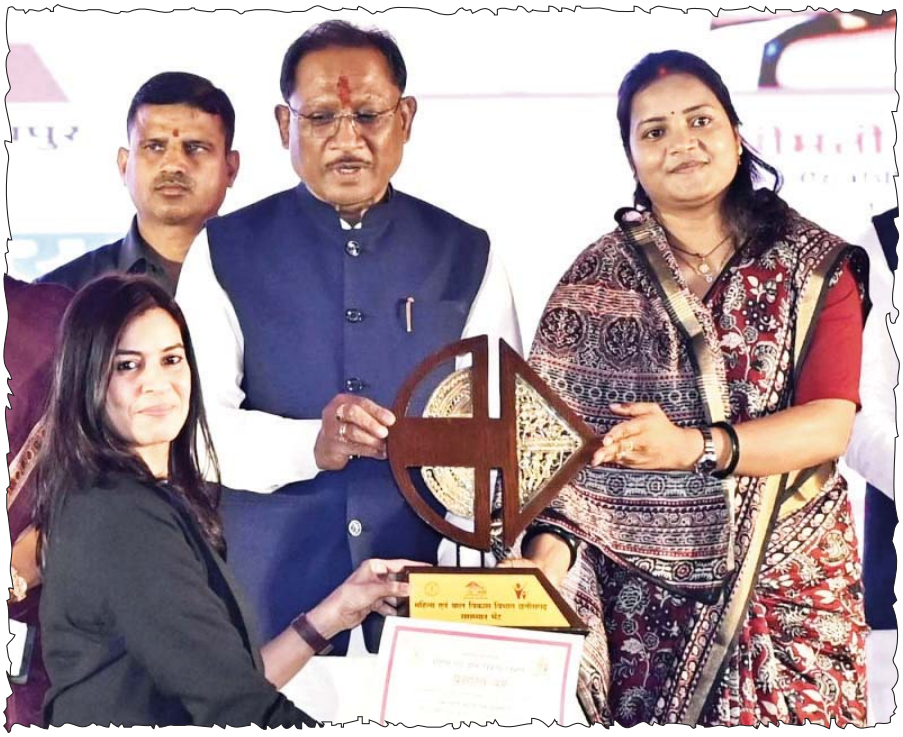

मुख्यमंत्री साय ने महिला पत्रकारों का किया सम्मान

रायपुर ▸▸ प्रदेश रौनक

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित महतारी वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में महिला पत्रकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ महिला पत्रकारों ने मीडिया में महिलाओं की भूमिका पर खुलकर चर्चा की। महिला पत्रकारों ने कहा कि महिला पत्रकार राजनीति, अपराध, खेल सहित हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं, बशर्ते उन्हें बराबरी का अवसर मिले। उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए बनाए जा रहे छात्रावासों की सराहना की और कहा कि यह पहल महिलाओं को घर से दूर भी सुरक्षित माहौल प्रदान करेगी। इससे अब अभिभावक अपनी बेटियों के करियर को लेकर निश्चिंत हो सकेंगे। उन्होंने पत्रकारों की सम्मान निधि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने के फैसले के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पत्रकारों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिला पत्रकारों ने मुख्यमंत्री निवास में सम्मान समारोह आयोजित करने पर खुशी जताई और कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे एक पिता ने हमें अपने घर बुलाया हो। उन्होंने कहा कि यह पहल महिला पत्रकारों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश में पहली बार इस तरह का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महिलाएँ समाज निर्माण की सशक्त धुरी हैं, और महिला पत्रकार अपनी लेखनी से सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। महिला पत्रकारों ने मुख्यमंत्री श्री साय के साथ लंच किया और उनके साथ सेल्फी भी ली। मुख्यमंत्री श्री साय ने महिला पत्रकारों के लिए भविष्य में नई योजनाओं पर विचार करने का भरोसा दिलाया और कहा कि सरकार महिला पत्रकारों को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

राजनांदगांव जिले को मिला पहला महिला थाना, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने किया शुभारंभ

राजनांदगांव. जिले में महिला दिवस पर पहला महिला थाना का उद्घाटन किया गया. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने फीता काटकर नए महिला थाना का शुभारंभ किया. जिला में नया महिला थाना खुलने से महिला प्रार्थी अपनी समस्या को आसानी से और बेझिझक रख सकेंगी. एसपी मोहित गर्ग ने उप निरीक्षक गीतांजली सिन्हा को नए थाने के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है. महिला संबंधित अपराधों की संजीदगी से जांच कर कार्यवाही को अंजाम तक पहुंचाने और महिलाओं की विशेष सुनवाई के साथ ही उन्हें न्याय दिलाने के लिए महिला थाने की शुरूआत की गई है. महिला थाना में 1 प्रभारी, 2 महिला प्रधान आरक्षक, 3 महिला आरक्षक और 1 नगर सैनिक की तैनाती की गई है. महिलाओं की शिकायतों की बेहतर ढंग से सुनवाई हो और अपराध पंजीबद्ध हो यही इस नए थाने का उद्देश्य है. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिला अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया.

गर्भवती माताओं को मिल रहा पौष्टिक व स्वादिष्ट मोदक लड्डू

प्रकृति की गोद में बसे कोरिया जिले में गर्भवती माताओं और उनके गर्भस्थ शिशुओं के पोषण को ध्यान में रखते हुए एक अनूठी योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन व नेतृत्व में जिला प्रशासन की पहल से 'मोदक लड्डू' निर्माण व वितरण की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत जिले की लगभग दो हजार गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन पौष्टिक मोदक लड्डू दिए जा रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जच्चा- बच्चा के पोषण स्तर को बढ़ाना और शिशु के जन्म के समय ढाई किलो वाले नवजात की समस्या को जन्म से पूर्व ही गर्भवती माताओं को सन्तुलित पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है।

स्वास्थ्य और परंपरा का अनूठा संगम-मोदक लड्डू-इस योजना के तहत बैकुंठपुर विकासखंड के ग्राम आनी में महिला स्व-सहायता समूहों की 25 महिलाएं प्रतिदिन 9 हजार से 10 हजार मोदक लड्डू तैयार कर रही हैं। यह लड्डू पूरी तरह से प्राकृतिक और पारंपरिक अनाजों से बनाए जा रहे हैं। सत्तू, रागी, बाजरा और ज्वार यानी चार तरह की लड्डू तैयार की जा रही है। इसमें गोंद, सोंठ, तिल, मूंगफली, इलायची और घी शामिल हैं। प्रत्येक लड्डू 30 ग्राम वजन का होता है, ताकि पोषण संतुलित बना रहे।डायटीशियन की देखरेख में तैयार किए जा रहे इन लड्डुओं में कैलोरी 139 केसीएएल, फैट 6.1ग्रा. कार्बोहाइड्रेट- 18 ग्रा.,डायटरी फाइबर 1.7 ग्रा., ऑयरन- 0.6 मिग्रा, प्रोटीन- 3.2 ग्रा., सैचरेटिड्- 2.2ग्रा., शुगर- 8.4 ग्रा., केल्शियम-45 मिग्रा, मैग्नेशियम-25 मिग्रा जैसे पोषक तत्व शामिल हैं, जो गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भस्थ शिशुओं के लिए बेहद लाभकारी हैं। इसके अलावा, लड्डू बनाने में मौसम का भी ध्यान रखा जाता है।

कैसे किया जा रहा है वितरण-प्रत्येक गर्भवती महिला को 15 दिन के लिए 30 मोदक लड्डू (प्रति दिन दो) दिए जाते हैं। लड्डू आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरित किए जाते हैं, जो महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्र तक नहीं आ सकतीं, उन्हें 'पोषण संगवारी' समूह की महिलाएं घर-घर जाकर लड्डू खिलाते हैं।

कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी की दूरदर्शी सोच-कलेक्टर ने बताया कोरिया जिले की अधिकांश गर्भवती महिलाओं को संतुलित और पौष्टिक आहार की आवश्यकता है। माताओं का अच्छा स्वास्थ्य ही स्वस्थ और मजबूत अगली पीढ़ी की नींव रखता है। इसी सोच के साथ हमने 'कोरिया मोदक' निर्माण व वितरण कार्य शुरू की है, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों को आवश्यक पोषण मिल सके। कलेक्टर ने बताया कि गर्भवती माताओं को प्रथम तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल एएनसी (एंटीनेटल केयर) जांच से गर्भावस्था के दौरान होने वाली गंभीर जटिलताओं का पता चलता है और इससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। इसीलिए यह जांच शत प्रतिशत किया जा रहा है साथ ही संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही हाई रिस्क ग्रुप (उच्च जोखिम) की गर्भवती महिलाओं एनीमिया, मधुमेह, हाइपरटेंशन, कम वजन आदि के सम्बंध में जानकारी प्राप्त की जाती है और ऐसी महिलाओं की विशेष देखभाल की जा रही है, जिससे जन्म लेने वाले शिशु ढाई किलो से अधिक हों साथ ही जच्चा-बच्चा स्वस्थ रहे। इन लड्डुओं में पारंपरिक और पोषणयुक्त सामग्री का समावेश किया गया है, जिससे गर्भवती महिलाओं की सेहत में सुधार होगा और कम वजन वाले नवजातों के जन्म की दर को कम किया जा सकेगा। यह प्रयास केवल माताओं के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

ग्राम रनई: जब महिलाओं ने खुद पंचायत की बागडोर

मानिकपुरी

कोरिया जिले को प्रकृति ने भरपूर प्यार दिया है। यहाँ की वादियां खूबसूरत है और तन-मन को अपनी ओर आकर्षित करने की अदभुत क्षमता है। लेकिन आज हम जिले के एक ऐसे गांव के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं, जो समाज व परिवार की सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एक विशेष रिपोर्टिंग! कोरिया जिले का ग्राम रनई इस बार के पंचायत चुनाव में एक नया इतिहास रचने में सफल रहा। यहां न केवल पंच-सरपंच निर्विरोध चुने गए, बल्कि खास बात यह रही कि ग्रामवासियों की सर्वसम्मति से पंचायत की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई। यह गांव महिला सशक्तीकरण की नई मिसाल पेश कर रहा है, जहां सरपंच सहित सभी 15 वार्डों की पंच महिलाएं हैं।

महिला नेतृत्व की ओर बढ़ता गांव

बैकुंठपुर विकासखंड से मात्र 15-16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम रनई की आबादी करीब 1800-1900 है। वर्षों से चली आ रही निर्विरोध चुनाव की परंपरा को इस बार भी कायम रखते हुए इस बार ग्रामीणों ने सभी पदों पर महिलाओं को निर्विरोध चुना है। दसवीं तक शिक्षित गांव की नव-निर्वाचित सरपंच श्रीमती बबीता ठाकुरिया ने बताया कि वे गांव की मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका पहला लक्ष्य महिलाओं के लिए स्नानघर और शौचालय का निर्माण कराना है, ताकि स्वच्छता और सुविधा को बढ़ावा दिया जा सके।

महिलाओं की प्राथमिकताएं और संकल्प

वार्ड पंच श्रीमती गीता शुक्ला और श्रीमती आशा दुबे ने बताया कि गांव में सार्वजनिक

महिला शौचालय का निर्माण कराया जाएगा

महिलाओं का सम्मान और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें

कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने कहा कि ग्राम रनई की यह उपलब्धि समस्त समाज को यह संदेश देती है कि महिलाएं जब ठान लें, तो हर बाधा को पार कर एक नए युग की शुरुआत कर सकती हैं, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जो महिलाएं नहीं कर सकती। इसलिए महिलाओं को अवसर की दरकार है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक महिलाओं का सम्मान करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें।

और पीने के पानी की समस्या को हल करने की दिशा में काम किया जाएगा। भूजल स्तर काफी नीचे होने के कारण बोरवेल से पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए पंचायत समुचित समाधान निकालेगी। इसके अलावा, निर्विरोध चुनी गईं अन्य महिला पंच श्रीमती सोनकुंवर, श्रीमती शशि, श्रीमती उपासना, श्रीमती श्यामबती, श्रीमती लीला, श्रीमती राधा साहू, श्रीमती लता, श्रीमती सुमित्रा पटेल, श्रीमती वेदमती, श्रीमती ज्योति, श्रीमती हीरामनी, श्रीमती चन्द्रमणि ने संकल्प लिया है कि वे गांव के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगी और वार्डवासियों के सुख-दुख में हमेशा उनके साथ खड़ी रहेंगी।

शराब और नशे के खिलाफ मुहिम

गांव की महिलाओं ने एक और क्रांतिकारी निर्णय लेने की बात कही। पंचायत की सभी महिलाएं एकजुट होकर शराब और अन्य मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों को लेकर जन-जागरूकता फैलाएंगी, जिससे समाज को इस बुराई से बचाया जा सके।

महिला शक्ति का प्रेरणादायक उदाहरण

ग्राम रनई का यह ऐतिहासिक निर्णय न केवल महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह पूरे जिले और प्रदेश के अन्य गांवों के लिए प्रेरणास्रोत भी बनेगा। जब महिलाएं स्वयं निर्णय लेती हैं और नेतृत्व की जिम्मेदारी उठाती हैं, तो बदलाव की राह स्वतः प्रशस्त होती है।

महिला खिलाड़ियों ने तोड़ दी हैं लैंगिक धारणाएं...

हमें महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण की शुरुआत समाज की सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक इकाई परिवार नामक संस्था से करनी चाहिए। परिवार में कभी भी अश्लील शब्दों और गालियों आदी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहीं से दिमाग में बीज डालने की शुरुआत होती है।

कमलेश गोगिया

रायपुर। आधी सदी बीत चुकी है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को, सन् 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को अधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। तब से पूरे विश्व में 8 मार्च को अंतर-राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर पुरुषों के दमखम वाले खेल के क्षेत्र में भी आधी सदी बिता देने वाली रायपुर की अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी कविता दीक्षित से वरिष्ठ पत्रकार डॉ. कमलेश गोगिया ने विशेष चर्चा की जिसमें उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी।

बकौल कविता दीक्षित, इतिहास के पन्ने इस बात की गवाही देते हैं कि महिलाओं ने लैंगिक आधार पर बनाई गई सारी धारणाओं को तोड़ दिया है और अपने मजबूत इरादों के साथ खेल के क्षेत्र में भी परचम लहरा रही हैं। पूरा देश जानता है कि भारतीय महिलाओं ने पुरुषों के दमखम वाले खेलों में भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है, वह ओलंपिक हो या कामनवेल्थ गेम्स और या फिर एशियन गेम्स, अनेक अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतें हैं और भारत का मान बढ़ाया है। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत को पहला पदक मनु भाकर ने ही दिलाया था। इसके पहले टोक्टो ओलंपिक 2020 मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला पदक जीता था। इसके भी पहले 2016 में हम देखें तो, देश को बेटियों ने ही गौरवान्वित किया था। रियो डी जनेरियो के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत को पहला पदक पहलवान साक्षी मलिक ने दिलाया था और दूसरा पदक बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जीता था। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत की स्टार शटलर सायना नेहवाल भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बनीं जिसने ओलिंपिक में मेडल हासिल किया था।

कविता दीक्षित का मानना है कि आम लोगों की तुलना में एक खिलाड़ी पर दोहरी भूमिका की जिम्मेदारी रहती है, खेल के साथ अन्य वह सब कुछ जिसका निर्वहन सामान्य रूप से एक आदमी भी करता है। बात यदि महिला खिलाड़ी की करें तो उस पर तिहरी जिम्मेदारी आ जाती है, घर और बाहर के साथ खेल के क्षेत्र में भी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देना।

आधी सदी से जारी है खेल का सफर

बैडमिंटन की अंतराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी रायपुर की कविता दीक्षित को पूरे 48 साल बीत चुके हैं बैडमिंटन में, मसलन आधी सदी बिता दी बैडमिंटन के खेल में। बकौल कविता, मुझे माँ से प्रेरणा मिली क्योंकि वे भी बैडमिंटन की खिलाड़ी थीं। मुझे बचपन से ही इस खेल से बहुत प्यार था। 10-11 साल की उम्र में पहली बार उसी वर्ष जूनियर स्टेट चैंम्पियन-शिप जीती। दो साल बाद फिर 1979 में स्कूल से नेशनल चैम्पियनशिप के लिए चयन किया गया। अगले साल 1980 में मध्यप्रदेश की जूनियर बैडमिंटन टीम के लिए चयन किया गया। तब, राज्य की टीम में चयन होना जिले के लिए गौरव की बात हुआ करती थी। उसी दौरान डिस्ट्रिक चैम्पयनिशप में सीनियर खिलाड़ियों को पराजित किया। फिर बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ती रही, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 39 साल पहले पहला इंटरनेशनल मैच रूस के खिलाफ खेला था। 1987 में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में स्पोर्ट्स कोटा के तहत सेवा का

अवसर मिला। कविता दीक्षित आल इंडिया इंटर इंस्टीट्यूशन, आल इंडिया पब्लिक सेक्टर सहित पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की रीजनल चैम्पियन रह चुकी हैं। कविता दीक्षित बीते एक दशक से भी ज्यादा समय से अंतर-राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर देश का मान बढ़ा रही हैं। इनमें ताइपेई-2007, ताइवान-2009, स्पेन-2011, कनाडा-2013, तुर्की, स्वीडन-2015, वर्ल्ड चैम्पयनशिप कोच्चि (कांस्य पदक), 2021- स्पेन और 2023 स:ाउथ कोरिया शामिल है। सन् 1984 से कविता दीक्षित बैडमिंटन का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही हैं। उहोंने राज्य व देश को अनेक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। इन उपलब्धियों के लिए वे अपने पति अनुराग दीक्षित को श्रेय देते हैं जिन्होंने विवाह के बाद भी कदम से कदम मिलाकर पूरा साथ दिया। श्री दीक्षित छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के सह सचिव और रायपुर जिला बैडमिंटन संघ के सचिव भी हैं। कविता दीक्षित भी छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ की सहसचिव हैं। पुत्र पार्थ दीक्षित टेनिस का प्रतिभावान राष्ट्रीय खिलाड़ी है।

समाज की सोच बदलना बाकी है

1977 में जब मैंने खेल शुरू किया तब खेल के क्षेत्र में महिलाओं को उतना एक्सपोजर नहीं मिलता था, समाज की सोच भी काफी संकीर्ण हुआ करती थी। आज वह स्थिति नहीं है, काफी जागरुकता आ गई है महिलाओं में, लेकिन समाज की सोच को बदलना अभी बाकी है। अब आप ही देखिए, हम साल में सिर्फ एक बार 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, जबकि मेरी सोच है कि हर दिन महिला दिवस चाहिए, सिर्फ एक दिन क्यों... अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के पैटर्न में बदलाव देखने को मिलता है। हम यह दिवस महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए मनाते हैं, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत गाँव की महिलाओं को है, शहर में तो ओवर-एक्सपोज की भी समस्या है। हर साल एक सिर्फ 8 मार्च को ही जागरुकता देखने को मिलती है, यदि हर दिम महिला दिवस मानें तो लोगों के विचार बदलेंगे और काफी कुछ सुधार भी आएगा।

हर महिला को होना चाहिए खिलाड़ी

अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी कविता दीक्षित वर्ष 2026 में एलआईसी से सेवानिवृत्त हो जाएंगी, लेकिन उन्हें देखकर उनकी आयु का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। श्रीमती दीक्षित के अनुसार, खेल का जुनून इनसान को भीतर से मजबूत कर देता है। एक खिलाड़ी हमेशा जवान ही रहता है, उसकी उम्र का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। मेरी तो यह सोच है कि हर महिला को कम से कम अपने जीवन में खिलाड़ी जरूर होना चाहिए क्योंकि खेल महिलाओं को न सिर्फ अनुशासन सिखाता है, बल्कि हार पचाने की भी ताकत देता है। महिलाओं को वैसे भी प्रकृति ने सहनशील बनाया है, क्योंकि नौ माह तक कोख की पीड़ा सहन करने की ताकत भी प्रकृति ने महिलाओं को ही दी है। सामान्य महिलाओं की तुलना में महिला खिलाड़ी ज्यादा मजबूत होती हैं। खेल के मैदान में वह हार-हार कर जीतना सीखती है और पूरी सहनशक्ति के साथ विवाह के बाद ससुराल जाती है।

परिवार में गालियाँ तो न बकें

कविता दीक्षित के मुताबिक, यह सच है कि महिलाओं को आज भी किसी न कसी मोर्चे पर अपनी अस्मिता की तलाश करनी पड़ती है। महिला अपराध आज इस एआई के युग में भी हो रहे हैं। हमें महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण की शुरुआत समाज की सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक इकाई परिवार नामक संस्था से करनी चाहिए। परिवार में कभी भी अश्लील शब्दों और गालियों आदी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहीं से दिमाग में बीज डालने की शुरुआत होती है। संचार के अत्याधुनिक माध्यमों ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। चाहे मोबाइल हो या टेलीविजन, आज हर घर में ओटीटी की सुविधा है और इसमें चलने वाली फिल्मों से लेकर धारावाहिकों तक में महिलाओं से संबंधित गालियाँ घरों तक पहुँच रही हैं, इस पर अंकुश लगाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ में उद्यमिता आयोग का होगा गठन : विष्णु देव साय

रायपुर ▸▸ प्रदेश रौनक

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में उद्यमिता आयोग के गठन की घोषणा की है। यह आयोग राज्य में उद्यमशीलता की संस्कृति को मजबूत करेगा और रोजगार सृजन की संभावनाओं का अध्ययन करेगा। इसके तहत युवाओं के कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण के लिए कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने यह घोषणा आज राजधानी रायपुर स्थित अग्रसेन धाम में स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए की। इस अवसर पर उन्होंने मंच की ऐतिहासिक यात्रा को समर्पित पुस्तक स्वदेशी की विकास यात्रा का विमोचन भी किया।

स्वदेशी अपनाना विकसित भारत की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम-मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत @2047 के निर्माण के लिए हमें स्वदेशी को आत्मसात करना होगा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच हमेशा से आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने की वकालत करता रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत एक विशाल और संपन्न देश है। यहाँ प्रचुर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, और साथ ही हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है। यह हमें न केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार प्रदान करता है, बल्कि नवाचार और औद्योगिकीकरण के लिए भी असीम संभावनाएँ खोलता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे बदलावों की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यवस्था में आ रहे परिवर्तनों को देखते हुए स्वदेशी जागरण मंच जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत की ओर-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया अभियान ने भारत में स्वदेशी उत्पादन को

बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को संरक्षण और समर्थन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि आज भारत लगभग हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है। हमने अपने उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया, उन्हें आवश्यक सुविधाएँ दीं और इसका परिणाम यह हुआ कि हम अब न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक बाजार में भी मजबूती से उभर रहे हैं।

नई औद्योगिक नीतिः रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता-मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को प्रदेश की प्राकृतिक संपदा और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। इस नीति में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है ताकि उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया जा सके। स्थानीय संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएँ भी चलाई जा रही हैं।

उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा, श्रेष्ठ उद्यमियों को किया गया सम्मानित-कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में सफल उद्यमियों को उद्यमिता प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि युवा और नवाचार आधारित स्टार्टअप्स को सरकार हर संभव सहायता देगी। बैठक में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री आर. सुंदरम, अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल, छत्तीसगढ़ प्रांत संयोजक श्री जगदीश पटेल, देश के प्रतिष्ठित उद्यमी, प्रोफेसर, कुलपति, आर्थिक विशेषज्ञ और स्वदेशी जागरण मंच तथा स्वावलंबी भारत अभियान के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

बस्तर क्षेत्र में स्वदेशी उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री श्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और विकास के लिए स्वदेशी जागरण मंच की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नई नीतियों और सुरक्षा बलों के प्रभावी प्रयासों के कारण नक्सलवाद अब बहुत सीमित क्षेत्र में सिमट गया है। अब समय आ गया है कि स्वदेशी जागरण मंच के सहयोग से इन क्षेत्रों में उद्योग-धंधे स्थापित किए जाएँ, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और वे नक्सलवाद की ओर न जाने पाएं।

बगिया में बच्चों संग मुख्यमंत्री ने मनाई रंगों की होली

बगिया ▶▶प्रदेश रौनक

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गांव के बच्चों के साथ होली का उत्सव हर्षोल्लास से मनाया और उनके संग रंगों की खुशियां साझा कीं। बगिया के मंझापारा गांव में होली के रंगों से सराबोर बच्चों का मुख्यमंत्री के प्रति उत्साह और अपनापन देखते ही बनता था, जब वे अपने गांव के पुरोधा और प्रदेश के मुखिया से मिलने उनके निवास पहुंचे, तो दृश्य किसी पारिवारिक उत्सव जैसा प्रतीत हुआ। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने निज निवास पर बच्चों की टोली का आत्मीय स्वागत किया और खुद भी उनके संग होली के रंगों में रंग गए। उनकी सहजता और सादगी ने बच्चों को बेझिझक उनसे मिलने और घुल-मिलकर बातचीत करने का अवसर दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने न केवल बच्चों से उनका हालचाल जाना, बल्कि उन्हें मिठाई खिलाई और उनके साथ ठहाके लगाते हुए हंसी-ठिठोली भी की। बच्चों ने बताया कि वे पूरे गांव में होली खेलते हुए मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं, और जब वे वहां पहुंचे, तो मुख्यमंत्री ने भी उनके संग पूरी

आत्मीयता से रंग-गुलाल खेला। यह मिलन एक अनोखे उल्लास का प्रतीक बन गया, जिसमें प्रेम, स्नेह और भाईचारे के रंग घुल गए। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि होली मेल-जोल, प्रेम और सौहार्द का पर्व है, जो समाज में भाईचारे को और भी मजबूत करता है। इस तरह के उत्सव हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत बनाए रखते हैं और हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं। गांव के बच्चों के उत्साह और मुख्यमंत्री की आत्मीयता ने इस होली को और भी यादगार बना दिया। यह अवसर केवल रंगों का नहीं था, बल्कि उसमें अपनत्व, स्नेह और खुशियों के अनगिनत रंग घुले हुए थे।

सुनीता विलियम्स धरती पर लौटीं

अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर अन्य दो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के ज़रिए पृथ्वी पर लौट आए हैं. बीते साल जून में महज़ आठ दिनों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए ये दोनों एस्ट्रोनॉट नौ महीनों बाद लौट पाए हैं. बोइंग का जो स्टारलाइनर यान उन्हें वापस धरती पर लाने वाला था वो ख़राब हो गया था इसलिए उन्हें इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा. उन्हें आख़िरकार एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित रूप से उतारा.

समुद्र में गिरने के बाद कैप्सूल के चारों ओर जिज्ञासु डॉल्फिनों का एक समूह चक्कर लगा रहा था. अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन से धरती पर पहुँचने में 17 घंटों का लंबा वक्त लगा. भारतीय समयानुसार तड़के 3 बजकर 27 मिनट पर चार अंतरिक्ष यात्रियों को लाने वाला कैप्सूल फ़्लोरिडा के तट के पास समंदर में गिरा.समंदर के सतह पर आने के बाद कंट्रोल सेंटर की ओर से अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत करते हुए कहा गया, निक, एलेक, बुच, सुनी...स्पेसएक्स की ओर से घर वापस आने का स्वागत है.

कमांडर निक हेग ने ख़ुशी ज़ाहिर करते हुए जवाब दिया, कैप्सूल सभी के चेहरे पर मुस्कुराहटों से भरा है.

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) से पृथ्वी तक आने का सफ़र लगभग 17 घंटे का था. पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ड्रैगन कैप्सूल की रफ़्तार 17000 मील प्रति घंटा थी जिसे कुछ मिनटों के अंतराल में तेज़ी से धीमा किया गया.इससे पहले मंगलवार को सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर के साथ दो और अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री लेग्ज़ेंडर गोर्बूनोव ने बाकी

अंतरिक्ष यात्रियों से विदा लिया था. निक हेग और गोर्बूनोव पिछले साल सितंबर में स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के ज़रिए छह महीने के अंतरिक्ष मिशन पर आईएसएस पर पहुंचे थे. जब कैप्सूल धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया था जोकि क़रीब तीन बजकर 20 मिनट पर फिर से बहाल हुआ.वायुमंडल में प्रवेश के बाद अंतरिक्ष यान के प्लाज़्मा शील्ड का तापमान 1927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था लेकिन हीट शील्ड सवार अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी तेज़ गर्मी से बचाने में मददगार साबित हुई.क़रीब 3 बजकर 21 मिनट पर अंतरिक्षयान ऑटोनोमस यानी स्वचालित हो गया था, यानी अंतरिक्ष यात्री इसे नियंत्रित नहीं कर रहे थे. इस दौरान उनके सामने लगे टच स्क्रीन पर वे सारी गतिविधियों को देख पा रहे थे. क़रीब तीन बजकर 24 मिनट पर पहले ड्रैगन कैप्सूल के दो पैराशूट खुले जिससे इसकी रफ़्तार और धीमी हो गई. इस दौरान एक ज़ोर का झटका लगा और कैप्सूल की रफ़्तार और धीमी हो गई.

जिस समय कैप्सूल समंदर में उतरा, उसके ठीक बाद ही पानी में कैप्सूल के चारों ओर डॉल्फ़िन चक्कर लगाती हुई तैरती दिखीं.

मौके पर मौजूद रिकवरी टीम फास्ट बोट्स से कैप्सूल तक पहुंची और पहले सुरक्षा का जायजा लिया और पैराशूट हटाया.इसके बाद स्पेसएक्स का रिकवरी पोत पहुंचा, जोकि लैंडिंग साइट से दो मील ही दूर पर रुका हुआ था. जिस

समय अंतरिक्ष यान की वापसी हो रही थी, आसमान पूरी तरह साफ़ नीला था. इसके बाद ड्रैगन कैप्सूल का साइड हैच खुला और सारी दुनिया अंतरिक्ष यात्रियों की झलक पाने का इंतज़ार करने लगी.इसके बाद नासा की लाइव तस्वीरों के ज़रिए दुनिया भर में लोगों ने सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को बाहर निकलते देखा.

क्रू के कैप्सूल से निकलने से पहले एक कैमरे ने अंदर की तस्वीरें खींची. इन तस्वीरों में सभी यात्री हाथ हिला कर अभिवादन करते दिखे. क्रू-9 के कमांडर निक हेग ड्रैगन से बाहर निकलने वाले पहले यात्री थे. वो बाहर निकले, कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराए, हवा में हाथ लहराए और आगे निकल गए. कैप्सूल से निकलने से ठीक पहले सुनीता विलियम्स और विलमोर ने कैमरे की ओर हवा में हाथ हिलाकर ख़ुशी ज़ाहिर की.अंतरिक्ष में क़रीब 286 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने धरती पर ताज़ा हवा में सांस ली. जिस समय वे कैप्सूल से बाहर आ रहे थे उनके चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी और कैमरे की ओर देखकर वे लगातार हाथ हिला रहे थे. क़रीब नौ महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए इन दोनों यात्रियों ने हर दिन 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखा और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इससे तालमेल बिठाना उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा. नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने बताया कि 'अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत ठीक है.'उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्री कुछ समय के लिए रिकवरी शिप पर रहेंगे और फिर उन्हें ह्यूस्टन ले जाया जाएगा. उन्होंने अपनी टीम का शुक्रिया कहा और 'नासा की ज़रूरतों के मुताबिक खुद को ढालने' के लिए अमेरिकी अरबपति एलमस्क की कंपनी स्पेसएक्स की तारीफ़ की. हालांकि अंतरिक्ष यात्रियों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी इसके बाद परिवार से मिलने की इजाज़त मिलेगी. आम तौर पर इसमें एक दिन का समय लगता है. स्टीव स्टिच ने कहा कि वे अंतरिक्ष में रहते हुए बिताए गए अपने समय के बारे में बात करेंगे और फिर छुट्टी पर चले जाएंगे. नासा स्पेस ऑपरेशन मिशन डायरेक्टर्स के डिप्टी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर्स जोएल मोंटालबानो ने कहा कि सुनी और बुच ने आईएसएस पर रहते हुए 900 घंटों तक रिसर्च किया और इस दौरान 150 वैज्ञानिक प्रयोग किए. उन्होंने नासा अंतरिक्ष यात्रियों के किए गए प्रयोगों को 'देश के लिए लाभदायक' बताया और उम्मीद जताई कि इस दशक के अंत तक मंगल ग्रह पर इंसान उतारने के नासा के लक्ष्य में ये मददगार साबित होंगे.

PM मोदी ने सुनीता विलियम्स के साथ शेयर की तस्वीर

सुनीता विलियम्स एक आइकन हैं- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा- ₹स्पेस रिसर्च का मतलब है मानवीय क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाना, सपने देखने का साहस करना और उन सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखना। सुनीता विलियम्स एक पथप्रदर्शक और एक आइकन हैं जिन्होंने अपने पूरे करियर में इस भावना का उदाहरण दिया है। हमें उन सभी पर बहुत गर्व है जिन्होंने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने दिखाया है कि जब सटीकता जुनून से मिलती है और तकनीक दृढ़ता से मिलती है तो क्या होता है।

नई दिल्ली। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर नौ महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद बुधवार तड़के (भारतीय समयानुसार) पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्री 5 जून 2024 को बोइंग के नए स्टारलाइनर क्रू यान में सवार होकर अंतरिक्ष गए थे और उन्हें एक हफ्ते में ही वापस लौटना था। हालांकि, यान में खराबी के कारण इन्हें अंतरिक्ष में ही रहना पड़ा। अंतरिक्ष से वापसी पर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को दुनियाभर से बधाई मिल रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों को बधाई देते हुए X पर लिखा है-₹आपका स्वागत है, #Crew9! धरती ने आपको याद किया।

दृढ़ता का वास्तव में मतलब दिखा- पीएम मोदी-भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- ₹आपका स्वागत है, #Crew9! धरती ने आपको याद किया। यह उनके धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रही है। सुनीता विलियम्स और #Crew9 अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि दृढ़ता का वास्तव में क्या मतलब है। उनका अटूट दृढ़ संकल्प हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगा।

सुनीता का भारत से रिश्ता-सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक और एस्ट्रोनॉट हैं। यह उनकी तीसरी अंतरिक्ष उड़ान थी। सुनीता ने अब तक अंतरिक्ष में कुल 608 दिन बिताए हैं। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड, ओहियो में हुआ था। उनके पिता दीपक पांड्या गुजरात के मेहसाणा जिले के झूलासन से संबंध रखते हैं। विलियम्स ने एक महिला द्वारा अंतरिक्ष में सर्वाधिक चहलकदमी किए जाने का रिकॉर्ड बनाया है।

पद्म भूषण से सम्मानित हैं सुनीता - सुनीता विलियम्स 2007 और 2013 समेत कम से कम तीन बार भारत आई हैं। सुनीता को साल 2008 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुनीता विलियम्स को एक पत्र लिखा था और उन्हें भारत की बेटी बताया था। पीएम मोदी ने सुनीता को भारत आने का निमंत्रण दिया था।

'31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा भारत'

नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (21 मार्च) को राज्यसभा को संबोधित किया। गृह मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि देश में पिछले 10 साल में वो काम हुए हैं, जो आजादी के बाद से अब तक नहीं हुए थे। इस बीच गृहमंत्री ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का वादा किया। उन्होंने पुरानी घटना याद करते हुए कहा कि एक समय पर उन्हें लाल चौक पर तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद से हर साल लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाता है। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने का जिक्र करते हुए कहा कि यह फैसला वोट बैंक के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और एकता के लिए लिया गया था। मोदी सरकार ने कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने का काम किया है। राज्यसभा में बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, '21 सदस्यों ने यहां अपने विचार प्रस्तुत किए। एक तरह से गृह मंत्रालय के अनेक कार्यों के आयामों को समेटने का प्रयास किया गया। सबसे पहले मैं देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ सीमाओं को मजबूत करने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हजारों राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।' अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकार भ्रष्टाचार रोकना ही नहीं चाहती थी। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं।

नक्सलवाद खत्म करने का वादा

गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में वादा किया कि 31 मार्च 2026 को देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद राजनीतिक समस्या नहीं है। इसे खत्म करना जरूरी है और एक साल के अंदर भारत सरकार इसे खत्म करके रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कर रही है, ताकि वहां के लोग मुख्य धारा के साथ जुड़ सकें। अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर की समस्या भी खत्म होने की कगार पर है, देश में हिंसक घटनाओं में 70 फीसदी की कमी आई है।

इस साल कितने नक्सली ढेर?

गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में अब तक 90 नक्सली मारे जा चुके हैं, 104 को गिरफ्तार किया गया है और 164 ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था, 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। 2004 से 2014 के बीच नक्सली हिंसा की कुल 16,463 घटनाएं हुई थीं, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014 से 2024 के बीच हिंसक घटनाओं की संख्या 53 प्रतिशत घटकर 7,744 रह गई हैं। इसी प्रकार, सुरक्षाबलों की मृत्यु की संख्या 1851 से 73 प्रतिशत घटकर 509 रह गई और नागरिकों की मृत्यु की संख्या 70 प्रतिशत की कमी के साथ 4766 से 1495 रह गई है।

आतंकवाद पर क्या बोले?

आतंकवाद और जम्मू कश्मीर को लेकर अमित शाह ने कहा, ''मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। पहले आतंकी हमलों के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती थी और लोग उन्हें भूल जाते थे। उरी और पुलवामा में भी आतंकी हमले हुए लेकिन हमने 10 दिन के भीतर ही पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की।'' उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 2019-24 के दौरान 40,000 सरकारी नौकरियां प्रदान की गईं, 1.51 लाख स्वरोजगार सृजित हुए, इसी दौरान कौशल क्लब भी चालू किए गए। मोदी सरकार के दौरान जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के कारण होने वाली मौतों में 70 प्रतिशत की कमी आई। इस दौरान आतंकवादी घटनाओं में भी भारी गिरावट आई। यहां आतंकवादी घटनाओं की संख्या 2004 और 2014 के बीच 7,217 से घटकर 2,242 (2014 और 2024 के बीच) हो गयी। उन्होंने कहा ₹5 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। अनुच्छेद 370 को निरस्त करके मोदी सरकार ने संविधान निर्माताओं के 'एक संविधान, एक झंडा' के सपने को पूरा किया। देश में एक ही प्रधानमंत्री, एक संविधान और एक झंडा हो सकता है।

गृह मंत्रालय में बदलाव पर क्या कहा?

अमित शाह ने कहा, ₹एक तरह से गृह मंत्रालय बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करता है। संविधान ने कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों को दी है। सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह एक सही निर्णय है। इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है, तो 76 साल बाद अब ऐसी स्थिति है कि कई तरह के अपराध राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रह गए हैं, वे अंतरराज्यीय भी हैं और बहुराज्यीय भी हैं - जैसे नारकोटिक्स, साइबर अपराध, संगठित अपराध गिरोह, हवाला। ये सभी अपराध सिर्फ एक राज्य के भीतर नहीं होते हैं। देश में कई अपराध देश के बाहर से भी होते हैं। इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय में बदलाव करना जरूरी हो जाता है। मैं यह गर्व के साथ कहता हूं कि 10 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय में लंबे समय से लंबित बदलाव एक बार में किए हैं।

चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर टीम इंडिया हुई मालामाल

दुबईः आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड की टीम ने टीम इंडियाको 252 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे उसने रोहित शर्मा की दमदार अर्धशतकीय पारी और श्रेयस अय्यर की 48 रनों की पारी से 1 ओवर पहले ही हासिल कर लिया। टीम इंडिया ने इससे पहले आखिरी बार 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था। ऐसे में एक बार फिर 12 साल बाद भारत ने आईसीसी के टूर्नामेंट को अपने नाम किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बाजी मारने वाली टीम इंडिया पर पैसों की बारिश हुई है। रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियन टीम इंडिया को प्राइज मनी के तौर पर 2.24 मिलियन डॉलर जो भारतीय करेंसी में 19.48 करोड़ है। सिर्फ टीम इंडिया ही नहीं, फाइनल में हारने

वाली कीवी टीम को भी करोड़ों रुपए मिले हैं। रनरअप रहने वाली न्यूजीलैंड को प्राइज मनी के तौर पर 1.12 यानी 9.74 करोड़ रुपए मिले हैं। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने फाइनल से पहले प्राइज मनी का ऐलान कर दिया था।आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ये पांच मोमेंट, जिन्हें दुनिया कई सालों तक भूल नहीं सकेगी. सेमीफाइनलिस्ट को भी मिला इनाम-सिर्फ विजेता और उपविजेता ही नहीं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में हारने वाली टीम को भी इनाम मिला है। चार टीमें आईसीसी के सेमीफाइनल में पहुंची थी, जिसमें भारत और न्यूजीलैंड ने फाइनल में जगह बनाई जबकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को हार मिली थी। ऐसे में नॉकआउट स्टेज तक पहुंची इन दोनों टीमों को 4.87 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि मिली है। वहीं ग्रुप स्टेज से बाहर रहने वाली टीम जो पांचवें और छठे स्थान पर रहने वाली अफगानिस्तान और बांग्लादेश को 3-3 करोड़ रुपए मिले हैं। सातवें और आठवें स्थान पर रहने वाली पाकिस्तान और इंग्लैंड को सिर्फ 1.22 करोड़ प्राइज मनी मिली है।

यूजीसी ने फिर किया अलर्ट, फर्जी यूनिवर्सिटी में न लें एडमिशन, बर्बाद हो जाएगा पूरा कैरियर

नई दिल्ली.बैंक हो, कोचिंग या मार्केट में खरीदारी.. फर्जीवाड़े की जड़ हर जगह पहुंच चुकी है. कुछ फर्जीवाड़ों में लोग रुपये गंवा बैठते हैं तो कुछ में अपना करियर. यूजीसी ने एक बार फिर से फेक यूनिवर्सिटी अलर्ट जारी किया है. इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले उसकी स्थापना से जुड़ी हर डिटेल अच्छी तरह से चेक कर लें. फर्जी यूनिवर्सिटी से मिलने वाली डिग्री भी फर्जी ही होती है.मान लीजिए कि आप हायर एजुकेशन के लिए किसी संस्थान में एडमिशन लेते हैं. 3, 4 या 5 साल वहां पढ़ाई करके अपनी डिग्री हासिल करते हैं. फिर जॉब या हायर स्टडीज के लिए कहीं जाते हैं और आपको यह कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपकी डिग्री तो फर्जी है! आप पर क्या बीतेगी? आपकी फीस, मेहनत सबकुछ एक झटके में बर्बाद हो जाएगा. इसलिए बेहतर है कि एडमिशन लेते समय ही आप अच्छी तरह से चेक कर लें कि यूनिवर्सिटी असली है या नकली.

किसी भी संस्थान में एडमिशन लेने से पहले ही चेक कर लेना चाहिए कि वह फर्जी है या असली. इससे आपकी सालों की मेहनत बर्बाद होने से बच जाएगी. जानिए कुछ टिप्स, जिनसे किसी भी यूनिवर्सिटी का फैक्ट चेक कर सकते हैं.

चेक करें यूजीसी की वेबसाइट-यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता देता है. यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.ugc.ac.in पर 'Universities' सेक्शन में विजिट करके मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो यह संदेह यानी शक वाली बात हो सकती है. यूजीसी समय-समय पर फर्जी यूनिवर्सिटी की सूची भी जारी करता है, जिसे आप चेक कर सकते हैं.

यूजीसी फेक यूनिवर्सिटी अलर्ट नोटिफिकेशन- एआई-सीटीई पर दें ध्यान-अगर आपकी यूनिवर्सिटी तकनीकी शिक्षा (जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट आदि) से संबंधित है तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) की वेबसाइट www.aicte-india.org पर विजिट करें. वहां अप्रूव्ड संस्थानों की लिस्ट उपलब्ध होती है. अगर आपके बीटेक कॉलेज का नाम नज़र आ रहा है तो वहां एडमिशन लेने का फैसला सही है. लेकिन अगर इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम मिसिंग है तो भूलकर भी वहां दाखिला न लें.

यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स- असली यूनिवर्सिटी की आमतौर पर एक प्रोफेशनल वेबसाइट होती है, जिसकी डिजाइन साफ-सुथरी होती है, सही संपर्क जानकारी (फोन नंबर, ईमेल, पता) और मान्यता संबंधी डिटेल्स होती हैं. अगर वेबसाइट में गलतियां, अधूरी जानकारी या स्टॉक फोटो ज्यादा दिखें तो सावधान होने की जरूरत है.

रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज पेपर (सेंट्रल) रूल्स 1956 के अंतर्गत प्रदेश रौनक मासिक पत्रिका के संबंध में स्वामित्व तथा अन्य विवरण विषयक जानकारी

घोषणा
(फार्म- IV)
(नियम)

1.	प्रकाशन स्थान	:	बाबा किराना स्टोर्स के पास,कालीनगर पंडरी,रायपुर (छ.ग.)
2.	प्रकाशन अवधि	:	मासिक
3.	मुद्रक	:	**सुजाता सोम**
	राष्ट्रीयता	:	भारतीय
	पता	:	बाबा किराना स्टोर्स के पास,कालीनगर पंडरी,रायपुर (छ.ग.)
4.	प्रकाशक का नाम	:	**सुजाता सोम**
	राष्ट्रीयता	:	भारतीय
	पता	:	बाबा किराना स्टोर्स के पास,कालीनगर पंडरी,रायपुर (छ.ग.)
5.	संपादक का नाम	:	**तुली मजूमदार**
	राष्ट्रीयता	:	भारतीय
	पता	:	आनंद नगर के पीछे सीएएसईबी आफिस बनरसी माना रायपुर, माना कैम्प,रायपुर (छत्तीसगढ़)
6.	पत्र का स्वामित्व भागीदार अथवा 1 प्रतिशत से अधिक पूंजी वाले हिस्सेदार	:	**सुजाता सोम**

मैं **सुजाता सोम** एतद् द्वारा घोषित करती हूं कि मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।
दिनांक 1 मार्च 2025

(सुजाता सोम)
प्रकाशक के हस्ताक्षर

अद्भुत इंजीनियरिंग का रहस्य समेटे घाघरा मंदिर

रायपुर ▸▸ प्रदेश रौनक

छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में स्थित घाघरा मंदिर अपने रहस्यमयी निर्माण और अनोखी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। बिना किसी जोड़ने वाले पदार्थ के सिर्फ पत्थरों को संतुलित करके बनाई गई इस प्राचीन संरचना का झुका हुआ स्वरूप इसे और भी रोचक बनाता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास और वास्तुकला का यह अनमोल रत्न आज भी अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए है।

जिले के मुख्यालय मनेंद्रगढ़ से लगभग 130 किलोमीटर दूर जनकपुर के पास स्थित इस मंदिर का रहस्य आज भी विशेषज्ञों के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है। सदियों पुराना यह मंदिर किसी चमत्कार से कम नहीं, जो बिना किसी गारा-मिट्टी या चूने के इस्तेमाल के आज भी मजबूती से खड़ा है।

घाघरा मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी निर्माण शैली है। इतिहासकार मानते हैं कि यह मंदिर पत्थरों को संतुलित करके इस तरह खड़ा किया गया है कि किसी भी प्रकार की जोड़ने वाली सामग्री की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यह तकनीक प्राचीन भारतीय वास्तुकला के अद्भुत कौशल को दर्शाती है। इस मंदिर का झुका हुआ स्वरूप इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। माना जाता है कि किसी भूगर्भीय हलचल या भूकंप के कारण इसका झुकाव हुआ होगा, लेकिन इसके बावजूद सदियों से यह मंदिर अपनी मजबूती के साथ खड़ा है।घाघरा मंदिर के निर्माण काल को लेकर विशेषज्ञ एकमत नहीं हैं। कुछ इतिहासकार इसे 10वीं शताब्दी का बताते हैं, तो कुछ इसे बौद्ध कालीन संरचना मानते हैं। वहीं, स्थानीय निवासियों का मानना है कि यह एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहां आज भी विशेष अवसरों पर पूजा-अर्चना होती है। मंदिर के भीतर किसी भी मूर्ति का न होना इसके रहस्य को और गहरा करता है। कई स्थानीय कथाओं के अनुसार, मंदिर का निर्माण उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग और तकनीकी कौशल का प्रमाण है।घाघरा मंदिर केवल श्रद्धालुओं का आस्था स्थल ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी अनमोल प्रतीक है। इस अद्भुत संरचना को देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक और शोधकर्ता आते हैं। पुरातत्वविदों के लिए भी यह मंदिर एक शोध का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस मंदिर को उचित पहचान दी जाए, तो यह स्थल धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन सकता है।मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी प्रमुख कस्बा जनकपुर है, जहां से घाघरा गांव आसानी से पहुंचा जा सकता है। मनेंद्रगढ़ से यहां तक का सफर लगभग 130 किलोमीटर का है। सड़क मार्ग के जरिए इस यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी लिया जा सकता है।

प्रगति पथ पर
छत्तीसगढ़
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
देश में धान की सर्वाधिक किस्मों वाला राज्य
प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता में देश का सबसे संपन्न राज्य
जैव विविधता के साथ हरियाली में अग्रणीय राज्य
कोयला उत्पादन में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य
देश के कुल सीमेंट उत्पादन में 20% का योगदान देने वाला राज्य
लौह अयस्क उत्पादन में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य
देश में टीन धातु का नंबर वन उत्पादक राज्य
सरप्लस बिजली उत्पादन के साथ देश का पावरहाउस
सुशासन से समृद्धि की ओर
ChhattisgarhCMO
DPRChhattisgarh
www.dprcg.gov.in
हमसे जुड़ने के लिए
QR स्कैन करें
संवाद आर.ओ.13156/246